

मनरेगा से श्रमिक प्रवासन पर पड़ने वाली प्रभाव एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

वंदना गोविन्दम्

गांव से शहर की ओर हो रहे पलायन को रोकने के लिये सरकार द्वारा पूर्व में अनेक प्रावधान किये गये हैं। सरकार की यह कोशिश है कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले। उन्हें गांव में शहर जैसी आधारभूत सुविधाएँ मिल सकें। केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना दो फरवरी 2006 को देश के 200 जिले में लागू किये गये। इस योजना के तहत चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन की अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना साथ ही पर्यावरण संतुलन पर भी ध्यान देना है। इस योजना से श्रम बाजार में मजदूरों की स्थिति सही हुई है। साथ ही ग्रामीणों का पलायन भी रुका है।